www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 297 | जौनपुर गुरुवार, 18 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

काशी के रविदास घाट पर हजारों लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

काशी, (एजेंसी)। पवित्र काशी में गंगा तट पर योग की महक फैल गई। 'गंगोत्री से गंगासागर' योग अभियान के तहत रविदास घाट पर मंगलवार 17 जून को एक भव्य योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, योग प्रेमियों और गंगा किनारे के लोगों ने एक साथ योगासन कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। इस अभियान का उद्देश्य मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर उनके संगम स्थल गंगासागर तक योग के संदेश को जन–जन तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा गंगोत्री से शुरू होकर गंगासागर तक चलेगी। आयुष मंत्रालय, आयुष मिशन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा यह अभियान विश्व योग दिवस (21 जून) की पूर्व संध्या पर एक सप्ताह तक चलेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि यह अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नदी किनारों, गांवों के अमृत सरोवरों, पौराणिक स्थलों, धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तथा पार्कों तक योग को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "समाज के हर वर्ग को योग से जोड़ना हमारा मुख्य लक्ष्य है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है"।

एसआईटी कर रही है अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान की चोरी के मामले की जांच

नई दिल्ली, (एजेंसी)।यूपी के अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपयों की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच, मंदिर के खजाने में कई और तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं. सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है. अयोध्या में श्रीराम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे के रूप में जमा हुए दान पात्रों की रकम में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद यहां इसी तरह की अन्य धांधली की खबरें भी आ रही हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर दी है जिसने जांच भी शुरू कर दी है लेकिन अब तक किसी के भी खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है.इस मामले में मंगलवार को पुलिस के पास कुल तीन शिकायतें पहुंची हैं. पहली शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने की, दूसरी शिकायत यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला और तीसरी शिकायत करणी सेना ने की है. लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है. वहीं विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से मामले की जांच कराने की मांग की है.

पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आया बड़ा बदलाव : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता, नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्वदेशी विनिर्माण के बल पर देश ने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि देश ने रक्षा उत्पादन और तकनीकी विकास के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए हैं। तीनों सेनाओं की क्षमताओं में हुआ विस्तार पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने वायु, भूमि और समुद्र तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। साथ ही स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। एक्स पोस्ट में कही यह बात प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "आत्मनिर्भरता की दृष्टि से निर्देशित और नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं स्वदेशी विनिर्माण द्वारा संचालित, भारत की रक्षा क्षमताओं में पिछले दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है।" उन्होंने कहा कि यह श्रृंखला पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति की एक झलक प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के विजन, नई तकनीक और स्वदेशी निर्माण ने भारत को मजबूती दी है।

स्वदेशी क्षमता से रणनीतिक महाशक्ति बनने की ओर भारत : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। यह बदलाव केवल सैन्य आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, रक्षा उत्पादन और वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक सुदृढ़ीकरण के रूप में सामने आया है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर अपनी एंटी–सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिनके पास ऐसी रणनीतिक क्षमता उपलब्ध है। इसके बाद 11 मार्च 2024 को मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत लंबी दूरी की ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो मल्टीपल वॉरहेड प्रणाली से लैस है और एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी–ड्रोन सिस्टम और एयरबोर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म जैसी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों ने भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। 23 अगस्त 2025 को डीआरडीओ ने एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया।

असम के कुछ जिलों में आबादी से अधिक आधार पंजीकरण, होगी जांच : सीएम हिमंत

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्य के कुछ जिलों में आधार नामांकन के आंकड़ों को लेकर चिंता जताते हुए दावा किया कि वहां जारी किए गए आधार कार्डों की संख्या अनुमानित आबादी से अधिक हो गई है। उन्होंने इसे सीमावर्ती राज्य के लिए "बड़ी जनसांख्यिकीय साजिश" का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असम के कुछ जिलों में आधार सैचुरेशन (नामांकन कवरेज) 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसका अर्थ है कि वहां अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने लिखा, "असम के कुछ जिलों में आधार नामांकन कुल आबादी से आगे निकल गया है, जो हमारे जैसे सीमावर्ती राज्य में एक बड़ी जनसांख्यिकीय साजिश की आशंका पैदा करता है।" हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने अयोग्य व्यक्तियों को आधार कार्ड मिलने से रोकने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आधार जारी करने पर विशेष प्रतिबंधा लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति आधार प्राप्त न कर सके, हमने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार जारी करने की प्रक्रिया पर कड़े प्रतिबंधा लगाए हैं।" मुख्यमंत्री ने एक ग्राफिक भी साझा किया, जिसमें कुछ जिलों में आधार सैचुरेशन 100 प्रतिशत से अधिक होने को "रेड फ्लैग" बताया गया। उनके अनुसार इसका सीधा मतलब है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मध्य प्रदेश दौरे से पहले हाई अलर्ट, ओंकारेश्वर में कड़े सुरक्षा इंतजाम

मध्य प्रदेश, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पांच दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विशेष रूप से ओंकारेश्वर के दो दिवसीय कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा इंतजामों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 जून को इंदौर से ओंकारेश्वर पहुंचेंगी। वहां आगमन के बाद वह पूजा–अर्चना करेंगी और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी। इसके बाद 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को सुचारू बनाने के लिए ओंकारेश्वर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। ये व्यवस्थाएं 17 जून की रात 12 बजे से 19 जून तक प्रभावी रहेंगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। राष्ट्रपति का इंदौर एयरपोर्ट पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इंदौर से ओंकारेश्वर तक उनकी यात्रा हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार अंतिम निर्णय मौसम की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। खंडवा के जिला मजिस्ट्रेट ऋषव गुप्ता ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि 18 और 19 जून को राष्ट्रपति का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से आम लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए प्रशासन का सहयोग करें ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारी वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है।

केजरीवाल का बड़ा आरोप- पेपर लीक अरबों का रैकेट, पैसा ऊपर तक जाता है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अरविंद केजरीवाल ने परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र द्वारा टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने और सेना के पेपर ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की आलोचना की है, इन कदमों को बेअसर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक अरबों का रैकेट है जिसका पैसा शीर्ष तक पहुंचता है, जिससे इन सतही उपायों पर सवाल उठते हैं। यह विवाद अधिनियम के तहत टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के बाद सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और इन उपायों को परीक्षा के पेपर लीक रोकने में बेअसर बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने टेलीग्राम पर पाबंदी और परीक्षा के पेपर हवाई मार्ग से पहुँचाने के लिए भारतीय सेना के इस्तेमाल को सरकार के बेतुके कदम बताया। उन्होंने सवाल किया कि सेना के विमानों से पेपर पहुँचाना, टेलीग्राम बंद करना... क्या इन कदमों से पेपर लीक रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि पेपर लीक का धंधा कई अरब रुपयों का रैकेट है। इसका पैसा सबसे ऊपर तक पहुँचता है। अगर पेपर लीक रुक गए, तो को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसीने 22 जून 2026 तक टेलीग्राम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसमें 2026 की दोबारा परीक्षा और उसके ठीक बाद का समय भी शामिल था। इस रोक का मकसद उस तरीके को रोकना था जिसके तहत राष्ट्रीय परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक के झूठे सबूत गढ़े जाते थे। टेलीग्राम के ब्म् पावेल डुरोव ने इस अस्थायी रोक की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लाखों आम यूजर्स को बिना वजह सजा मिलती है, जबकि लीक को रोकने में भी यह नाकाम रही है, क्योंकि लीक अब दूसरे ऐप्स पर हो रहे हैं। उन्होंने ग पर कहा कि भारत के प्ब् मंत्रालय ने एक हफ्ते के लिए टेलीग्राम पर रोक लगा दी क्योंकि कुछ यूजर्स ने परीक्षा के लीक हुए सवाल शेयर किए थे।

मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय से मिले पीयूष गोयल, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और मोनाको के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात कर स्थिरता, ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने बताया कि उनकी मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय के साथ हुई बैठक में भारत–मोनाको साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श हुआ। उन्होंने नीस में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम की भी जानकारी दी, जिसने भारत के जीवंत प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। केंद्रीय मंत्री ने नीस में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले तीन दिनों में हासिल उपलब्धियां भारत–फ्रांस नवाचार साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व तथा 'भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' की साझा दृष्टि ने इस सहयोग को नई दिशा दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं, सीईओ, निवेशकों और नवोन्मेषकों को भारत के साथ मिलकर नवाचार आधारित और सतत भविष्य के निर्माण के लिए काम करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक साझेदारों के लिए नए अवसरों का केंद्र बनकर उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने फ्रांस के ग्रास शहर स्थित प्रतिष्ठित फ्रैगोनार्ड फैक्ट्री का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इत्र और सुगंध उद्योग की ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा।

तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1.28 लाख रुपये का कर्ज, विजय सरकार का श्वेत पत्र

विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति पर जारी एक श्वेत पत्र के अनुसार, तमिलनाडु की कुल वित्तीय देनदारियां बढ़कर अनुमानित 13.18 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, और राज्य का बकाया प्रत्यक्ष कर्ज 10 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा पेश की गई वित्तीय स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ लगभग दोगुना हो गया है और तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर असल में 1.28 लाख रुपये का कर्ज है। तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पर श्श्वेत पत्रश जिसमें पिछली एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार से मिली वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। विजय द्वारा पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद की गई पहली बड़ी घोषणाओं में से एक था। डॉक्यूमेंट के अनुसार, राज्य का सीधा कर्ज पांच साल पहले के लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर अभी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जब ऑफ–बजट उधार, गारंटी और दूसरी देनदारियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो राज्य पर कुल वित्तीय बोझ का अनुमान 13.18 लाख करोड़ रुपये लगाया जाता है। मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में जमा हुआ कर्ज, उससे पहले के छह दशकों में जमा हुए कुल कर्ज से भी ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि उधार का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाने के बजाय रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल किया गया है। तमिलनाडु का बकाया कर्ज–ळैक्च अनुपात 28.2 प्रतिशत है, जबकि पिछले पांच सालों में रेवेन्यू घाटा 46,538 करोड़ रुपये से बढ़कर 78,324 करोड़ रुपये हो गया है,।

भारतीय लोकतंत्र को कर रहे बर्बाद : जयराम रमेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष पर हमला करने और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। क्योंकि इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने पर उन्हें मिली अपमानित हार का बदला लिया जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में परिसीमन विधेयकों को पारित कराने में विफल रहने के बाद मिली अपनी अपमानजनक हार की भरपाई के लिए विपक्ष पर अपना हमला जारी रखे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। रमेश ने एक्स पर आरोप लगाते हुए कहा, उनके प्रलोभन उन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो महज दो साल पहले भाजपा विरोधी मजबूत एजेंडे पर चुने गए थे। अब वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें कथित तौर पर दिए जा रहे प्रोत्साहन चौंका देने वाले हैं। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री एक पूरी तरह से निंदनीय अभियान चला रहे हैं, जो सुनियोजित है और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप विभिन्न योजनाएं और उत्पाद पेश करता है। रमेश ने जोर देकर कहा उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वह अपने अंतिम लक्ष्य में सफल नहीं होंगे। उनकी यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के मंगलवार देर रात के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र से सांसदों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जा रहा है, जिससे पार्टी के लोकसभा सदस्यों के एक वर्ग के पाला बदलने की तेज अटकलों को और बल मिला है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तर्ज पर संभावित विद्रोह की अटकलें तब और मजबूत हो गईं जब सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने असंतुष्टों का स्वागत करने और पार्टी बदलने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता देने का संकेत दिया। जब शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और उद्धव के करीबी राउत दिल्ली गए तो लोगों की भौंहें तन गईं, जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि वे पार्टी के नौ सांसदों द्वारा अलग समूह बनाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं।

संपादकीय

भारत विरोधी रुख

यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के साझा बयान में भारत के नजरिए से कई आपत्तिजनक बातें हैं। यूक्रेन युद्ध के साथ कश्मीर का उल्लेख और कश्मीर को अनसुलझा मुद्दा बताना स्पष्टतरू भारत विरोधी रुख है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पिछले हफ्ते हुई चीन यात्रा के समय जारी साझा बयान में जम्मू–कश्मीर का जिक्र हुआ। चीन ने जम्मू–कश्मीर को इतिहास से जन्मा विवाद कहा। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे के शांतिपूर्ण और उचित समाधान की बात कही। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, द्विपक्षीय समझौतों, और संबंधित पक्षों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। स्पष्टतरू यह भारत विरोधी बयान था। उचित ही भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कश्मीर संबंधी उन टिप्पणियों को सिरे से ठुकरा दिया। बहरहाल, अब यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने पाकिस्तान के साथ अपने साझा बयान में जो कहा है, वह चीन की टिप्पणियों से भी आगे जाता मालूम पड़ा है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काया काल्लास की इस्लामाबाद यात्रा के समय जारी वक्तव्य में कहा गया– श्पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर मुद्दे की जानकारी दी। ईयू ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने इन टकरावों का संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुरूप बातचीत एवं कूटनीति से शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया।च स्पष्टतरू इस कथन में कई आपत्तिजनक बातें हैं। यूक्रेन युद्ध के साथ कश्मीर का उल्लेख और कश्मीर को अनसुलझा मुद्दा बताना सीधे तौर पर भारत विरोधी रुख है। यहां तक कि चीन ने भी भारत– पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौतों का उल्लेख किया था, जबकि ईयू ने उनकी भी अनदेखी कर दी है। एक अलग टिप्पणी में काल्लास ने पाकिस्तान को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बताया। पिछले कई दशकों से भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के संरक्षक पाकिस्तान को अलग–थलग करना रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद इस दिशा में कई अहम कामयाबियां भी मिली थीं। मगर अब पाकिस्तान को क्यों अहमियत एवं अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता मिल रही है, यह कठिन प्रश्न हमारे सामने है। चीन और 57 सदस्यों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन का हाथ तो हमेशा पाकिस्तान की पीठ पर रहा है, मगर ईयू और अमेरिका के डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी उसे अहमियत दें, तो क्या इसे भारतीय विदेश नीति की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाएगा?

जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका दिखा अलग थलग, दुनिया जता रही मोदी पर भरोसा

नीरज

जी–7 शिखर सम्मेलन इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार का मंच नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का आईना प्रतीत हुआ। फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनके सामने वह यूरोप खड़ा था जो अब आंख मूंदकर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं दिखता। लंबे समय तक टैरिफ की धमकियां, कूटनीतिक दबाव, सार्वजनिक अपमान और अचानक फैसलों का सामना करने के बाद अब यूरोपीय देशों ने यह मान लिया है कि ट्रंप बदलती अमेरिकी सोच का स्थायी चेहरा हैं। यही कारण है कि इस बार जी–7 सम्मेलन पर सबसे गहरी छाया अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरी की रही। देखा जाये तो ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक बेचौनी ने इस सम्मेलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई को लेकर चिंता गहरा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के मोड में पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रंप इस सम्मेलन में यह साबित करने पहुंचे कि उनकी आक्रामक और टकराव वाली विदेश नीति परिणाम दे रही है। वह चाहते हैं कि दुनिया अमेरिकी प्राथमिकताओं को स्वीकार करे, चाहे मामला व्यापार का हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, सुरक्षा का या फिर चीन को घेरने की रणनीति का। लेकिन इस बार यूरोप का स्वर बदला हुआ है। वह अमेरिका के साथ तो रहना चाहता है, मगर उसकी हर बात पर सिर झुकाने को तैयार नहीं है। देखा जाये तो यूरोप के भीतर यह बदलाव अचानक नहीं आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वर्षों से यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मैक्रों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह ऐसा समय है जब अमेरिकी, रूसी और चीनी नेतृत्व यूरोप के हितों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए यूरोप को अब जागना होगा और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। हालांकि मैक्रों की रणनीति केवल विरोध की नहीं है। उन्होंने ट्रंप के साथ निजी संबंध बनाए रखने की भी भरपूर कोशिश की है। कभी एफिल टावर पर भोज, कभी सैन्य परेड में विशेष सम्मान और कभी नोट्रे डेम कैथेड्रल के पुनरोद्धार समारोह में आमंत्रण देकर उन्होंने ट्रंप को साधने की कोशिश की है। लेकिन ईरान युद्ध और ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप में ट्रंप विरोध चरम पर पहुंच गया। एक समय तो हालात ऐसे बन गए थे कि यूरोपीय नेताओं को लगने लगा कि ट्रंप डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं। यह केवल एक भू–राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उस भरोसे के टूटने का प्रतीक था जिस पर दशकों से अटलांटिक गठबंधन टिका हुआ था। दरअसल, ग्रीनलैंड प्रकरण ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। यही कारण है कि अब यूरोपीय देशों में यह बहस तेज हो गई है कि अगर अमेरिका हर वैश्विक संकट में नेतृत्व नहीं करता या करना नहीं चाहता, तो आगे की दुनिया कैसी होगी। इस चिंता ने नाटो और अटलांटिक गठबंधन की नींव तक को हिला दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इस बार दबाव में दिखे। घरेलू राजनीति में चुनौती झेल रहे स्टारमर को ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन न करने के कारण ट्रंप की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन का मजाक उड़ाया और उसे असहयोगी तक कह दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका के और करीब जाने की कोशिश कर रहा ब्रिटेन अब फिर यूरोप की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें कभी ट्रंप का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता था, वह भी अब दूरी बनाती नजर आ रही हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुईं और उन्होंने अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिम एशिया के बीच संवाद की कड़ी बनने की कोशिश की। साफ है कि दुनिया अब केवल अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर रहने की बजाय बहुध्रुवीय

संतुलन की तरफ बढ़ रही है। देखा जाये तो ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि वह निजी कूटनीति को सार्वजनिक तमाशे में बदल देते हैं। पिछले वर्ष नाटो प्रमुख मार्क रुटे के निजी संदेश सार्वजनिक कर उन्होंने यह दिखा दिया था कि यूरोपीय नेता निजी तौर पर अमेरिका के दबाव को स्वीकार करते हैं, भले ही सार्वजनिक मंचों पर विरोध का अभिनय करें। इस कारण अब यूरोपीय नेताओं के लिए संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट रखना है और अमेरिका से रिश्ते भी नहीं बिगाड़ने हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सम्मेलन में विशेष महत्व रखती है। जब पश्चिमी दुनिया भीतर से विभाजित दिखाई दे रही है, तब भारत एक ऐसे संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है जिस पर हर शक्ति केंद्र भरोसा करना चाहता है। मोदी ने रूस और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखे, पश्चिम एशिया के संकटों में संतुलन साधा और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिर नेतृत्व वाली निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है। देखा जाये तो मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने भारत को किसी एक खेमे में सीमित नहीं होने दिया। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी कायम रखी और रूस के साथ पुराने रिश्ते भी नहीं टूटने दिए। पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकार्यता बनी रही और यूरोप के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग भी लगातार बढ़ता गया। जी–7 जैसे मंचों पर मोदी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत केंद्र में आ चुका है। जब दुनिया अविश्वास, टकराव और अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत संवाद, संतुलन और स्थिरता का चेहरा बनकर उभरा है। यही प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहरहाल, जी–7 शिखर सम्मेलन 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गहरे मतभेदों और पश्चिमी देशों के भीतर बढ़ती अविश्वास की राजनीति के बावजूद संवाद की प्रक्रिया टूटी नहीं। ईरान संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हुए तनाव, तेल आपूर्ति को लेकर आशंकाओं और यूक्रेन युद्ध की लंबी खिंचती स्थिति के बीच सदस्य देशों ने कम से कम इस बात पर सहमति दिखाई कि बहुपक्षीय सहयोग को जिंदा रखना जरूरी है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और विकासशील देशों के कर्ज संकट जैसे मुद्दों पर साझा चर्चा आगे बढ़ी। यूरोप ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का स्वर बुलंद किया, जबकि अमेरिका ने भी यह संकेत दिया कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों में अधिक भागीदारी निभानी होगी। भारत, ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भागीदारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल साउथ को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों की आकांक्षाओं को मजबूती से उठाकर भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया। हालांकि सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर ठोस नतीजे देने में विफल भी रहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई निर्णायक रोडमैप सामने नहीं आया।

भारत में रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण जरूरी

नंतू

भारत पर्यटन गाइड दुनिया के कई तेल उत्पादक देश, जैसे सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, लीबिया और मलेशिया, अपने नागरिकों को वैश्विक मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस पर भारी सब्सिडी देते हैं। ये देश मूल्य नियंत्रण या प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के माध्यम से ऊर्जा की कीमतों को अपेक्षाकृत कम बनाए रखते हैं और अक्सर तेल राजस्व का उपयोग वैश्विक मूल्य वृद्धि के झटके को सहने के लिए करते हैं। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में बार–बार बढ़ोतरी चिंतनीय है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने का रास्ता चुना है, जबकि इसका सीधा बोझ देश के लगभग 33.7 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। यह तब है जब वित्त वर्ष 2025–26 में सरकारी तेल कंपनियों ने संयुक्त रूप से 77,280.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 130 प्रतिशत अधिक है। अकेले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 36,802 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया।7 जून से 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई। यह तीन महीनों के भीतर दूसरी बढ़ोतरी है। इस वर्ष अब तक कुल बढ़ोतरी 89 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुकी है। दूसरी ओर, पिछले वर्ष पेट्रोलियम क्षेत्र से करों और शुल्कों के रूप में सरकार को लगभग चार लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। दुनिया के कई तेल उत्पादक देश, जैसे सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, लीबिया और मलेशिया, अपने नागरिकों को वैश्विक मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस पर भारी सब्सिडी देते हैं। ये देश मूल्य नियंत्रण या प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के माध्यम से ऊर्जा की कीमतों को अपेक्षाकृत कम बनाए रखते हैं और अक्सर तेल राजस्व का उपयोग वैश्विक मूल्य वृद्धि के झटके को सहने के लिए करते हैं। ईरान में ईंधन की कीमत दुनिया में सबसे कम मानी जाती है और वहां सरकार अरबों डॉलर की सब्सिडी देती है।वेनेजुएला भी आर्थिक और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद अत्यंत कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराता है। सऊदी अरब घरेलू ऊर्जा लागत को स्थिर और किफायती बनाए रखने के लिए हर वर्ष 12 अरब डॉलर से अधिक की सब्सिडी देता है। लीबिया में पेट्रोल, डीजल और गैस पर दुनिया की सबसे अधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे कभी–कभी सीमा पार तस्करी जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। मलेशिया अपने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले आरओएन 95 ईंधन पर भारी सब्सिडी देता है, हालांकि हाल के वर्षों में वित्तीय दबाव कम करने के लिए प्रति नागरिक सब्सिडी वाली मात्रा पर सीमा निर्धारित की गई है।इसके विपरीत, दुनिया में सबसे अधिक गरीब आबादी वाले देशों में शामिल भारत में प्रत्यक्ष ईंधन और गैस सब्सिडी का दायरा सीमित है। सरकार की बहुचर्चित उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यह सुविधा अब साल में केवल चार सिलेंडरों तक सीमित कर दी गई है। इसके लिए वार्षिक बजट आवंटन लगभग 12,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस मद में सरकार का वास्तविक व्यय कितना है, यह बहुत कम लोगों को पता है। योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में वर्तमान में केवल 6.52 करोड़ परिवार ही बीपीएल श्रेणी में आते हैं।हर बार जब एलपीजी की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के घाटे का तर्क सामने रखा जाता है। जबकि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां देश की प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं और सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। इन कंपनियों में सरकार की नियंत्रक हिस्सेदारी है। इनके अलावा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी अन्य सरकारी कंपनियों की भी इनमें हिस्सेदारी है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम तेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जबकि आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में कार्य करती हैं। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में अलग–अलग भूमिकाएं निभाने के बावजूद ये सभी कंपनियां एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का संयुक्त शुद्ध लाभ लगभग 42,650 करोड़ रुपये रहा।पेट्रोलियम क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है। अनुमान है कि यह क्षेत्र केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग 14 प्रतिशत और राज्यों के अपने कर राजस्व का लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान सरकारी तेल कंपनियों ने मिलकर 4.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, जिसमें जिसमें 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केंद्र सरकार को प्रॉफिट पेट्रोलियम और सरकारी कंपनियों के लाभांश आदि के रूप में प्राप्त हुई। प्रॉफिट पेट्रोलियम से आशय तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से प्राप्त लाभ में सरकार की हिस्सेदारी से है। इसके अलावा ये कंपनियां कॉरपोरेट कर, उत्पाद शुल्क और वैट का भुगतान करती हैं तथा सरकार को नियमित रूप से बड़ा लाभांश भी देती हैं। ऐसे में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रसोई गैस की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के लिए हर बार तेल विपणन कंपनियों के कथित घाटे का सहारा लिया जाता है। एलपीजी केवल एक वाणिज्यिक उत्पाद नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए भोजन पकाने की बुनियादी जरूरत है। सरकार इस विषय की संवेदनशीलता को समझती है। यही कारण है कि चुनावों से पहले आम तौर पर तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से बचा जाता है। हाल में ईरान और खाड़ी क्षेत्र में तनाव तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल के बावजूद हाल ही में संपन्न तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों से पहले घरेलू तेल कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों और परिवहन लागत में बढ़ोतरी के कारण अधिकांश देशों की तरह भारत भी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

स्वस्थ भारत, सशक्त भारत-स्वास्थ्य देखभाल विकास के 12 वर्ष

श्रीमती अनुप्रिया पटेल

बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली से आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, कार्यबल की संख्या में बढ़ोतरी होती है और विकास दीर्घावधि तक होता है। इसलिए, अच्छी सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति भी है। यह वह आधार है, जिस पर मानवीय क्षमता का निर्माण होता है और देश की ताकत मापी जाती है। इसलिए, बेहतर सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति है और इसमें लगाया गया हर रुपया देश के लोगों में किया गया निवेश है। इस तरह, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) , यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग, चाहे उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बिना किसी आर्थिक परेशानी के, जब और जहाँ जरूरत हो, अच्छी गुणवत्ता की सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकें। यह न केवल 2030 तक हासिल किया जाने वाला सतत् विकास का लक्ष्य है, बल्कि सेहत से जुड़ी एक प्राथमिकता भी है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी 2017), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) और एसडीजी 3 को हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है और यह एक सरल लेकिन मजबूत सोच पर आधारित है –स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए। इसके चार स्तंभ, किफायती होना, पहुँच, गुणवत्ता और उपलब्धता , उस सोच को वास्तिवकता में बदलते हैं और जीवन के सभी चरणों में देखभाल की एक व्यापक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली का एक एकीकृत तीन–स्तरीय मॉडल प्रदान करने में मदद करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों (कमजोर वर्गों सहित) के बीच दोतरफा रेफरल लिंक शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्राथमिक स्तर पर बीमारी से बचाव, सेहत को बढ़ावा देने, इलाज, पुर्नवास और प्रशामक देखभाल जैसी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं। ईसंजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म इन एएएम के जरिए समुदाय को विशेषज्ञों से जोड़कर विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही, एक खास टेली–मानस प्लेटफॉर्म भी है, जिसने अब तक कुल 38.93 लाख लोगों तक पहुँच बनाई है। एएएम से जुड़े द्वितीय स्तर के केंद्र जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)ध्प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) और जिला अस्पताल (डीएच) होते हैं, जो विशेषज्ञ के समक्ष इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के लिए रेफरल का पहला जरिया होते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे तृतीयक संस्थान सबसे ऊपर होते हैं और ज्यादा जटिल व सुपर–स्पेशलिस्ट सेवाओं की जरूरतें पूरी करते हैं। इस तीन–स्तरीय प्रणाली को सरकारी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी का समर्थन प्राप्त है। पिछले दशक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर होने वाला खर्च 168त्न बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सफर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से समस्या होने से पहले ही ध्यान रखने वाली देखभाल की ओर जरूरी बदलाव को दिखाता है। व्यापक स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करना, भारत की बदलती आबादी और बीमारियों के बदलते पैटर्न के हिसाब से उठाया गया एक जरूरी कदम है। बढ़ती उम्र की आबादी और गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, इसके दायरे में गैर–संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन सेवाएँ, आँख, कान–नाक–गला (ईएनटी) और मुँह की सेहत के साथ–साथ योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। यह सब उस आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो भारत अब बन रहा है। मई 2026 तक, देश भर में 1.8 लाख से ज्यादा एएएम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। इस विस्तार का असर एएएम में 120 करोड़ से ज्यादा ओपीडी परामर्श, 70 करोड़ से ज्यादा ईसंजीवनी टेली–परामर्श और अच्छी सेहत व कल्याण को बढ़ावा देने वाले 46.1 करोड़ से ज्यादा वेलनेस सत्रों में साफ दिखता है। प्राथमिक देखभाल स्तर पर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आम कैंसर (जैसे ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर) के लिए आबादी–आधारित स्क्रीनिंग 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्कों के लिए की जाती है, जिससे बीमारी का जल्दी पता लगाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। यह जांच आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत सेवा वितरण का एक अहम हिस्सा है, जो एनसीडी की रोकथाम को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करती है। एनसीडी सेवाओं का विस्तार बीमारी का जल्दी पता लगाने, रोकथाम, प्रबंधन और इलाज के लिए एक बहु स्तरीय प्रयास है।

भारत की जैव-विविधता- प्रतिबद्धताएँ और उपलब्धियाँ

भारत की जैव विविधता का संचालन त्रि स्तरीय संरचना पर आधारित है। इसके तहत यह संरचना जैव विविधता की राष्ट्रीय नीति को राज्य स्तरीय कार्रवाई और स्थानीय स्तर के क्रियान्वयन से जोड़ती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है जबकि राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित जैव विविधता परिषद प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर इन्हें निर्देशित करते है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन कमेटियां लोगों की जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती है और सामुदायिक स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देती है। भारत में अभी तक करीब 276653 जैव विविधता कमेटियों का गठन हुआ है.और करीब 272648 जैव विविधता रजिस्टर निर्मित किये गए है जिनमें समूचे देश की अनेक स्थानीय प्रजातियों, पारिस्थितिकी और परंपरागत ज्ञान का दत्तावेजीकरण किया गया है। कुल मिलाकर ये संस्थाएं और इनकी कार्य प्रक्रियाएं हमें वैश्विक स्तर की जैव विविधता के पारिस्थितिकी संतुलन से तालमेल बिठाने में मदद करती है। एक लचीले भविष्य के लिए प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण जैव–विविधता भारत की पर्यावरणीय और विकास प्राथमिकताओं का केंद्र है। यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक संतुलन का समर्थन करती है। भारत के वन, आर्द्रभूमि, पर्वत, समुद्री तट, मरुस्थल, घास के मैदान और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विविध प्रजातियों और समुदायों को बनाए रखते हैं। लाखों स्थानीय समुदाय दैनिक जीवन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। भारत नीतियों, संस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैश्विक ढांचों के अनुरूप अपनी प्राकृतिक पूंजी और जैव–विविधता प्रतिबद्धताओं को बनाए रखता रहता है। इन प्रयासों के माध्यम से भारत श्वक जैव–विविधता लक्ष्यों में योगदान देता है और राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर संरक्षण को मजबूत करता है। भारत का दृष्टिकोण स्थानीय प्रबंधन पर जोर देता है, क्योंकि यह माना जाता है कि समुदाय–नीत कार्रवाई व्यापक जैव–विविधता परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। पिछले दशक में, भारत ने वैज्ञानिक प्रबंधन, आवास पुनर्स्थापना, प्रजाति पुनर्वास कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर जैव–विविधता संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, वन्यजीव मॉनिटरिंग को मजबूत करना, अवक्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्स्थापन और जैविक संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों ने पारिस्थितिक लचीलापन बढ़ाया है, स्थानीय आजीविका का समर्थन किया है और जैव–विविधता संरक्षण में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। संरक्षण लक्ष्यों को स्थायी विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करके, भारत भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित करने और समावेशी व पर्यावरण–जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। जैव–विविधता को समझना और उसका महत्व जैव–विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और वे पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं जो इसे बनाते हैं। यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है और परागण, मृदा निर्माण, पोषक चक्र, जल शुद्धिकरण और जलवायु नियमन जैसे प्रमुख पारिस्थितिकी सेवाओं का समर्थन करती है। जैव–विविधता प्राकृतिक तंत्रों को बनाए रखती है जो जीवन को संभव और उत्पादक बनाते हैं। जैव–विविधता पर्यावरण और मानव समाजों दोनों के स्वास्थ्य के लिए केंद्रित है। व्यावहारिक रूप से, जैव–विविधता वही है जो पारिस्थितिकी तंत्रों को कार्यशील, लचीला और लोगों का समर्थन करने योग्य बनाती है। जैव–विविधता की रक्षा केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भारत जैसा पारिस्थितिक रूप से विविध देश के लिए एक विकास प्राथमिकता भी है। क्या आप जानते हैं ? जीन को वंशागति की मूल इकाई माना जाता है। जीन माता–पिता से संतान को संप्रेषित होते हैं और भौतिक व जैविक लक्षणों को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, रेड एप्पल, ग्रैनी स्मिथ एप्पल और गोल्डन एप्पल सेब के विभिन्न सांख्यिकीय भिन्न हैं। वहीं, प्रजाति एक जीवों का समूह है जो सफलतापूर्वक प्रजनन करके प्रजनन क्षमता वाली संतति उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रजाति परिभाषा प्रजनन के आधार पर जानवरों, पौधों और जीवन के अन्य रूपों को समूहों में विभाजित करती है। उदाहरण के लिए, बाघ, शेर और गैंडा अलग–अलग जानवर प्रजातियाँ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव, तथा मौसम और परिदृश्य मिलकर जीवन बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित कारक और अजीव कारक दोनों होते हैं। जीवित कारकों में पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल हैं। अजीव कारकों में चट्टानें, तापमान और आर्द्रता शामिल हैं। भारत का जैव–विविधता ढांचा भारत का जैव–विविधता ढांचा संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए कानूनों, नीतियों, संस्थाओं और कार्यक्रमों को मिलाता है। यह न्यायसंगत लाभ साझाकरण को भी बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वैश्विक जैव–विविधता प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है। जैव–विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) जैव–विविधता अधिनियम, 2002 भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा है जो जैव–विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लिए है। यह राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर जैव–विविधता शासन के लिए सांविधानिक आधार प्रदान करता है। यह कानून जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का भी समर्थन करता है। यह पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए भी प्रावधान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि जैविक संसाधनों के उपयोग को ऐसे संसाधनों के प्रदाताओं के लिए न्यायसंगत वापसी से जोड़ा जाए। क्या आप जानते हैं? व्यावहारिक रूप से, भारत के ढांचे के तहत, पारंपरिक ज्ञान जैविक संसाधनों और उनके उपयोग (खाद्य, आयुर्वेद, कृषि, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभ्यासों) के बारे में समुदाय–रखी गई ज्ञान को कवर करता है, जो पीढ़ियों से संप्रेषित होता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रथागत अभ्यासों के साथ निकटता से जुड़ा होता है। जैव–विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इस ढांचे को और मजबूत किया है, जिससे कार्यान्वयन अधिक सुविधाजनक और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप हो गया है। यह शोध, नवाचार और पारंपरिक ज्ञान–आधारित अभ्यासों का समर्थन करता है और अनुपालन और शासन कुशलता में सुधार करता है। संशोधन सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय जैव–विविधता दस्तावेजीकरण को भी मजबूत करता है, जो प्रभावी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलकर, अधिनियम और उसका संशोधन भारत के जैव–विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए एक संतुलित कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर : कृपाशंकर सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल एवं जनसेवा को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज "12 साल बेमिसाल" कार्यक्रम के तहत विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के परशुरामपुर मंडल के ग्राम सभा अभयचंद पट्टी निवासी सतेंद्र चौहान के आवास पर पहुंचकर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जौनपुर कृपाशंकर सिंह ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद परशुरामपुर के विनोद शर्मा एवं उतरेजपुर के संजय यादव को

सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृपाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणों को दी आगे कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर भी चर्चा की गई। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता, तकनीकी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजबूत अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी राजकुमार गौड़ का भी अभिनंदन किया तथा उनके प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सभाजीत चौहान, जयशंकर पाल, श्याम राज सिंह, मंडल अध्यक्ष परशुरामपुर सुरेंद्र मिश्रा, महेंद्र चौहान, राजकुमार, मुकेश साहू, अनीश मिश्रा (मंडल मंत्री), सिकंदर सोनकर, वीर बहादुर चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

बीबीएयू में वर्मी–कम्पोस्टिंग स्टेशन का शुभारंभ, 'शून्य अपशिष्ट परिसर' बनाने की दिशा में बढ़ा कदम

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कम्पोस्टिंग एवं वर्मी–कम्पोस्टिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। पर्यावरण विज्ञान विभाग एवं नवकल्पना प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने ग्रीन हाउस के पीछे स्थापित इस इकाई का फीता काटकर उद्घाटन किया। यह पहल पर्यावरण विज्ञान विभाग की शोधार्थी रोशिनी बजाज द्वारा डॉ. जीवन सिंह और प्रो. शिखा के मार्गदर्शन में विकसित की गई है।उद्घाटन समारोह में कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को भविष्य में व्यावसायिक स्तर तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि इसके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया जा सके और इसे सतत उद्यमिता का सफल मॉडल बनाया जा सके। उन्होंने शोधार्थी रोशिनी बजाज के प्रयासों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में भी दृढ़ इच्छाशक्ति, समर्पण और नवाचारी सोच के बल पर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान रोशिनी बजाज ने वर्मी–कम्पोस्टिंग इकाई में तैयार की गई जैविक खाद का नमूना कुलपति को भेंट किया। कुलपति ने विद्यार्थियों और शोधार्थियों से नवाचार आधारित स्टार्टअप विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजनकर्ता बनाना भी है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के लिए 14.16 लाख रुपये की स्वीकृति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 14.16 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल से विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के लिए जारी की गई यह धनराशि महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने, उन्हें आधुनिक एवं टिकाऊ खेती की तकनीकों से जोड़ने तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से खर्च की जाएगी।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उनका उद्देश्य महिलाओं को केवल कृषि श्रमिक के रूप में नहीं, बल्कि सफल किसान और उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि महिला किसानों की आय में वृद्धि और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है।

बड़े मंगल पर सेवा, श्रद्धा और समरसता के रंग में रंगीं महापौर सुषमा खर्कवाल

लखनऊ, (संवाददाता)।ज्येष्ठ माह के पावन बड़े मंगल के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आस्था, सेवा और जनकल्याण का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों, सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारों में सहभागिता करते हुए भगवान हनुमान के चरणों में श्रद्धा–सुमन अर्पित किए। उन्होंने प्रदेश एवं लखनऊवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए बड़े मंगल की परंपरा को लखनऊ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक बताया। महापौर ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज के गेट संख्या–4 पर आयोजित ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल के विशाल भंडारे से की। यहां उन्होंने श्रद्धालुओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि धार्मिक एवं सेवा भावना से जुड़े ऐसे आयोजन समाज में सामाजिक समरसता, सहयोग और मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। उन्होंने आयोजन के सफल संचालन के लिए कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दीं।इसके बाद महापौर आवास विकास पार्किंग क्षेत्र स्थित पंचवटी स्वीट्स के सामने भूतनाथ मार्केट सर्राफा एसोसिएशन द्वारा आयोजित विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम में पहुंचीं। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद वितरित किया और कहा कि बड़े मंगल की परंपरा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है।

अधूरे हाईवे पर हादसों में जान गंवाने वालों की स्मृति में निकला कैंडल मार्च

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। चंदवक थाना अंतर्गत वाराणसी–आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग–233 के अधूरे निर्माण के चलते वर्षों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में क्षेत्रीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वांचल किसान संगठन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा। कैंडल मार्च गाजीपुर रोड स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल से शुरू होकर चंदवक चौराहा स्थित गांधी पार्क तक निकाला गया। इस दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल किसान संगठन के अध्यक्ष एवं किसान नेता अजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग–233 के निर्माण में केराकत तहसील क्षेत्र का लगभग 16 किलोमीटर हिस्सा अब भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जबकि इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। इससे आम लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण पूरा किए बिना टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। उनका कहना था कि अधूरे निर्माण के कारण पिछले वर्षों में करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने मांग की कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए अथवा नो–एंट्री की व्यवस्था लागू की जाए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने तथा दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। इस अवसर पर सुजीत सिंह, जैकेश भास्कर, महेंद्र प्रजापति, जय प्रकाश राम, रामेश्वर सिंह, अरविंद पांडेय, संदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जौनपुर में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विकास भवन परिसर के सामने तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव तथा भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सैमुअल पाल, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विकास, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को चित्रों एवं सूचना पटलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही जनपद में हुए प्रमुख विकास कार्यों को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में अवसंरचना विकास के तहत निर्माणाधीन पांच फैमिली कोर्ट भवन, केराकत एवं शाहगंज के नौली में अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। वहीं "खेलेगा जौनपुर, जीतेगा उत्तर प्रदेश" थीम के अंतर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकसित सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं खेल सुविधाओं के विस्तार को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया है। इसके अलावा बदलापुर में 5.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बस स्टेशन सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की झलक प्रस्तुत की गई है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कोविड काल में निःशुल्क वैक्सीन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

समेकित जन कल्याण एंव जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत प्राकृतिक खेती कार्यशाला का कार्यक्रम सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होन के उपलक्ष पर समेकित जन कल्याण एंव जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत प्राकृतिक खेती कार्यशाला एंव त्वरित मक्का विकास योजना के अन्तर्गत किसान गोष्ठी/प्रदर्शनी का आयोजन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के सभागार में सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम में अध्यक्ष गो सेवा आयोग उ०प्र० श्याम बिहारी गुप्ता, विधायक मिल्कीपुर चन्द्रभानु पासवान , कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज डा० ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भा०ज०पा० राधेश्याम त्यागी, महानगर अध्यक्ष भा०ज०पा कमलेश श्रीवास्तव, कृष्णा चौधरी राष्ट्रीय सम्पर्क प्रमुख लोक भारती एंव सदस्य कृषि समृद्धि आयोग, डा0 अनिल कुमार यादव, मण्डलीय टास्क फोर्स अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोन्मुखी) उ०प्र०, डा० पी०के० कनौजिया उप कृषि निदेशक, अयोध्या, डा० सौरभ वर्मा, जिला कृषि अधिकारी अयोध्या, जिला उद्यान अधिकारी, डा० आर०बी० सिंह निदेशक प्रसार, डा० बी०पी० शाही वरिष्ठ वैज्ञानिक विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र मसौधा, डा०एस० पी० सिंह, प्राध्यापक, एंव अन्य सहयोगी विभागों यथा–उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य, आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारीगण तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राकृतिक खेती के प्रगतिशील किसान तथा जनपद से प्रगतिशील कृषकगण उपस्थित रहे। कार्यशाला एंव गोष्ठी/प्रदर्शनी का शुभारम्भ अध्यक्ष गोसेवा आयोग उ०प्र० एंव अन्य अतिथिगणों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आये हुए जन प्रतिनिधियों एंव अधिकारियों को पुष्प गुच्छ एंव अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। डा० श्याम बिहारी गुप्ता जी द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती कर किसान भाई स्वंय एंव धरती को स्वस्थ रख सकते है जिसके लिये आवश्यक है कि गो संरक्षण किया जाय और गोमूत्र एंव गोबर को बेकार न करें उससे विभिन्न प्राकृतिक खेती हेतु उपयोगी चीजो को बनायें। किसान भाई बायो गैस की स्थापना करें सरकार की तरफ से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है तथा लक्ष्य भी बढ़ाया जा रहा है। डा ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह कुलपति जी द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय में माडल खेती को विकसित किया गया है और प्राकृतिक खेती में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उत्पाद जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी आदि का लाइव डेमो प्रदर्शनी स्थल पर है किसान भाई देखकर सीखें तथा किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित कर निदान पायें। चन्द्रभानु पासवान विधायक मिल्कीपुर द्वारा किसान भाइयों से अनुरोध किया कि वैज्ञानिकों एंव विशेषज्ञों द्वारा बतायी गयी विधाओं के अनुसार प्राकृतिक खेती को अवश्य अपनायें। राधेश्याम त्यागी द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती करते आये है और अब पुनः प्राकृतिक खेती किये जाने की आवश्यकता है ताकि स्वस्थ एंव खुशहाल जीवन रहें। कृष्णा चौधरी द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में अपने विचार प्रकट किये गये। डा० एस०पी० सिंह प्राध्यापक द्वारा प्राकृतिक खेती के सिद्धान्त एंव विधि में प्रयुक्त सामग्री के बारे में विस्तार से बताया। डा० कामिनी सिंह मोरिंगा लेडी आफ उ०प्र०, श्री बृजेश सिंह हाथरस, राकेश दूबे अयोध्या आदि किसानों द्वारा अपने अपने प्राकृतिक खेती के अनुभवों का साझा किया। जनपद में प्राकृतिक खेती पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 23 प्रगतिशील किसानों को प्रशिस्त पत्र, अंगवस्त्र देकर मा० अध्यक्ष गोसेवा आयोग एंव मा० कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया। अन्त में डा० पी०के० कनौजिया ने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों/कृषकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्राचीन दुर्गा मंदिर की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों ने लगाया जाम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित जफराबाद थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। विरोध में ग्रामीणों ने जफराबाद–बेलाव मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। ग्रामीणों के अनुसार, करीब 200 वर्ष पुराना यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गुरुवार सुबह लगभग 6रू30 बजे गांव निवासी हरिओम पाठक ने मंदिर में प्रतिमा को सुरक्षित देखा था। करीब 8रू30 बजे सखोई गांव निवासी उमेश अग्रहरि दर्शन के लिए पहुंचे तो प्रतिमा खंडित मिली। आरोप है कि अराजक तत्व प्रतिमा को मंदिर से हटाकर गोमती नदी किनारे फेंक गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और दोषियों की गिरफ्तारी तथा नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष जफराबाद मिथिलेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता भी मौके पर पहुंचे उनके साथ जलालपुर थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह और गौराबादशाहपुर थानाध्यक्ष गंगाराम मिश्र भी मौजूद रहे। सीओ सिटी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के सहयोग से नई दुर्गा प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी तथा घटना में शामिल व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के विरोध में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय नाविकों पर किए गए कथित हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की और केंद्र सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। वामपंथी दलों के नेताओं ने कहा कि भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर यह तीसरा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के विपरीत कार्य कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमेरिका अपनी वैश्विक दादागीरी कायम रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की पारंपरिक स्वतंत्र विदेश नीति कमजोर हुई है और सरकार अमेरिका के प्रति अपेक्षित कड़ा रुख अपनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकों की मौत पर प्रभावी विरोध दर्ज न कर पाना देश की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए चिंताजनक है। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिससे ऊर्जा कीमतों, उर्वरकों और आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ रही है। वामपंथी दलों ने मांग की कि भारत सरकार अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराए, मृत भारतीय नाविकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए तथा दोषियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वामपंथी दलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

चकमार्ग निर्माण की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा किसान, प्रशासन ने शुरू कराया निर्माण कार्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित खुटहन थाना क्षेत्र के शेख असरखपुर गांव में गुरुवार को चकमार्ग निर्माण की मांग को लेकर एक किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। किसान ने चेतावनी दी कि यदि उसी दिन चकमार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो वह टावर से कूदकर जान दे देगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गांव निवासी सतीश कुमार यादव का आरोप है कि गांव के मुख्य मार्ग से जुड़ा लगभग 400 मीटर लंबा चकमार्ग राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे जोतकर अपने खेतों में मिला लिया है। उनका कहना है कि वह पिछले एक वर्ष से चकमार्ग खाली कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार सुबह करीब सात बजे सतीश कुमार यादव नहर के पास स्थित मोबाइल टावर पर करीब 50 फीट ऊंचाई तक चढ़ गए। सूचना मिलते ही एसडीएम शाहगंज कुणाल गौरव, क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने टावर के नीचे जाल और गद्दे बिछा दिए। करीब तीन घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रशासन ने मौके पर चकमार्ग की पैमाइश कराई और जेसीबी मशीन लगाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद किसान टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। किसान के सकुशल नीचे आने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। एसडीएम कुणाल गौरव ने बताया कि चकमार्ग से संबंधित मामले का नियमानुसार समाधान कराया जाएगा।

महानगर पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर, चोरी की पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के महानगर क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक शातिर अपराधी निकला, जिसके खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गैंगस्टर और अन्य गंभीर अपराधों के कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार इरसाद अहमद ने थाना महानगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल संख्या यूपी–32 जेबी–8773 (पैशन प्रो) 18 फरवरी 2026 को गजल आइसक्रीम के सामने स्थित दारू वाली गली से चोरी हो गई थी। मामले में थाना महानगर में मुकदमा संख्या 102/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।मंगलवार को थाना महानगर पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल लेकर दो व्यक्ति स्मृति वाटिका की ओर से उत्तराखंड पार्किंग होते हुए हनुमान सेतु मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी।कुछ देर बाद दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर वाहन के कागजात मांगे, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने स्वीकार किया कि यही वह मोटरसाइकिल है जिसे उन्होंने 18 फरवरी को महानगर क्षेत्र से चोरी किया था।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक रस्तोगी निवासी कौशलपुरी, छोटा भरवारा, चिनहट तथा नर सिंह पुत्र गया प्रसाद निवासी विराज खंड, गोमतीनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली।पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आदी हैं। विशेष रूप से अमित कुमार रस्तोगी का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है।

नवागत सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय देवाशीष उपाध्याय ने संभाला कार्यभार

अयोध्या।बुधवार को नवागत सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय आयुक्त देवाशीष उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण किया।कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर जिले से स्थानांतरित होकर आये नवागत सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय आयुक्त देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित जांच,सैंपलिंग एवं प्रवर्तन कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा।बताया कि खाद्य कारोबारियों व मिष्ठान व्यवसायी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के साथ–साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर विशेष जांच अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा तथा विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करेगा।उन्होंने लोगो से अपील किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी किसी भी शिकायत की सूचना विभाग को दें,ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवागत सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त को बुके देकर उनका स्वागत किया तथा जनपद में खाद्य सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।

'जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्थानीय निकायों की समीक्षा बैठक'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' विगत दिवस विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में स्थानीय निकायों की समीक्षा बैठक सम्पन्न की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों द्वारा संचालित विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जन शिकायतों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी के साथ प्रभावी बनाया जाए तथा नियमित सफाई, कूड़ा उठान और नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से ही कर ली जाएं। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्तापूर्ण

चेक करने निर्देश दिए तथा अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को बंधन योजना की यूसी अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए तथा प्राप्त जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय आमजन से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राजस्व दीपाली भार्गव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, संबंधित उप जिला जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

अयोध्या जनपद का सोहावल क्षेत्र बना महिला नेतृत्व का प्रेरक मॉडल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर अब केवल नारों तक सीमित नहीं है।बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है।अयोध्या जनपद की सोहावल तहसील इसका सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है,जहां शासन–प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और नगरीय निकायों के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं।इससे आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी के साथ सुशासन को भी नई दिशा मिल रही है।सोहावल तहसील की एसडीएम सविता सिंह राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि न्यायिक एसडीएम पूर्णिमा सिंह न्यायिक मामलों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।नायब तहसीलदार रेशु जैन भी राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन कर रही हैं।स्वास्थ्य विभाग में सीएचसी की अधीक्षक डा0 अर्चना वर्मा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कर रही हैं, वहीं सीडीपीओ अनीता सोनकर महिला एवं बाल विकास योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में जुटी हैं।इसके अलावा आपूर्ति निरीक्षक पूजा सिंह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी कर रही है।खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगी हैं।नगर पंचायत खिरौनी की अधिशासी अधिकारी आरती श्रीवास्तव नगरीय विकास कार्यों को गति दे रही हैं,जबकि उपनिबंधक नम्रता त्रिपाठी पंजीकरण संबंधी कार्यों का संचालन कर रही हैं।एक ही तहसील क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की सक्रिय मौजूदगी सामाजिक बदलाव और महिला नेतृत्व की नई इबारत लिख रही है।स्थानीय लोगों का मानना है कि महिला अधिकारियों की कार्यशैली में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है,जिससे जनसमस्याओं के समाधान में भी तेजी आई है।सोहावल आज महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण का एक प्रेरक मॉडल बनकर सामने आ रहा है।

भारत के सीमेंट ब्रांडों पर आधारित पुस्तक एबीसी आफ सीमेंट ब्रांडस इन इंडिया - पास्ट, प्रजेंट एंड फ्यूचर का हुआ लोकार्पण

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।भारतीय सीमेंट उद्योग के वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं लेखक डॉ. के. एन. झा द्वारा लिखित पुस्तक ष्एबीसी आफ सीमेंट ब्रांडस इन इंडिया रू पास्ट, प्रजेंट एंड फ्यूचर का लोकार्पण गुरुवार को नोएडा में आयोजित एक समारोह में किया गया।पुस्तक का लोकार्पण मंजू देवी कनोडिया,विशाल कनोडिया एवं गौतम कनोडिया (संस्थापक, कनोडिया समूह) द्वारा किया गया।इस अवसर पर भारतीय सीमेंट उद्योग के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद, डॉ. के. मोहन तथा प्रसिद्ध टेक्नो–लीगल सलाहकार एवं कॉर्पोरेट एडवाइजर श्री विजय सरदाना विशेष रूप से उपस्थित रहे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. के. मोहन ने कहा कि भारत का सीमेंट उद्योग देश के आर्थिक एवं आधारभूत संरचना विकास के साथ निरंतर विकसित हुआ है और आज यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक उद्योग बन चुका है। तकनीक, गुणवत्ता, स्थिरता और ब्रांड निर्माण के क्षेत्र में हुए परिवर्तन इस उद्योग की सफलता की कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. झा की यह पुस्तक सीमेंट उद्योग के विकास को ब्रांडों के दृष्टिकोण से समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री विजय सरदाना ने कहा कि यह पुस्तक सीमेंट उद्योग से जुड़े पेशेवरों, निवेशकों, नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं, सलाहकारों एवं विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होगी।पुस्तक में यह बताया गया है कि किस प्रकार ब्रांड बनाए जाते हैं, विकसित होते हैं, समय के साथ स्वयं को पुनर्स्थापित करते हैं तथा कुछ ब्रांड प्रतिस्पर्धा में पीछे भी रह जाते हैं।लेखक डॉ. के.एन. झा ने पुस्तक की विषय–वस्तु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें वर्ष 1914 से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय सीमेंट उद्योग की विकास यात्रा का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुस्तक में उन 80 से अधिक सीमेंट ब्रांडों का भी विश्लेषण किया गया है जो समय के साथ बाजार से विलुप्त हो गए। साथ ही उन अग्रणी उद्योगपतियों और प्रमोटरों के योगदान को भी रेखांकित किया गया है जिन्होंने अपने ब्रांडों को चार दशकों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक स्थापित एवं प्रासंगिक बनाए रखा।उन्होंने बताया कि पुस्तक में बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा उभरते हुए निजी सीमेंट ब्रांडों की यात्रा और चुनौतियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।अंतिम अध्याय में भारतीय सीमेंट उद्योग के भविष्य, नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास की संभावनाओं पर विशेष चर्चा की गई है।इस अवसर पर सीमेंट उद्योग के अनेक वरिष्ठ पेशेवर एवं अधिकारी, जिनमें बाबूलाल सिंह, आशुतोष शुक्ला एवं आर.एन. मालू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।बताते चले कि डॉ. के. एन. झा सीमेंट उद्योग के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं और उन्हें इस क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने ब्रांडिंग, ग्रामीण विपणन एवं सीमेंट उद्योग से संबंधित कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया है।

'केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समेकित जन–कल्याण एवं जन–जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास भवन परिसर में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ माननीय कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह, विधायक ददरौल अरविंद कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष के0सी0मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, विनीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रदर्शनी में केन्द्र सरकार के विगत 12 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के साथ–साथ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं लोकहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा आमजन के जीवन स्तर में सुधार हेतु किए गए प्रयासों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।

अतिथियों ने प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा परिसर में स्थापित सेल्फी स्टैंड पर फोटो खिंचवाकर कार्यक्रम में सहभागिता की। प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा जनहित में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदर्शनी में योजनाओं से संबंधित साहित्य, सूचना सामग्री एवं जन–जागरूकता संदेश भी प्रदर्शित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि यह प्रदर्शनी आगामी तीन दिनों तक आमजन के लिए लगी रहेगी। नागरिक अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं लोकहितकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करें तथा पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर पीडी डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह, डीसी मनरेगा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों ने एडीए के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन

अयोध्या।सदर तहसील के गंजा और मलिकपुर गांव के किसानों ने एडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया।इस मौके पर सैकड़ों किसान अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान किसानों और उपाध्यक्ष के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई।किसानों ने जमीन अधिग्रहण की आशंका जताते हुए विरोध दर्ज कराया।किसानों का दावा है कि पहले अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि गांव की शेष जमीन नहीं ली जाएगी।हाल ही में सामने आए एक पत्राचार से किसानों में नई आशंका पैदा हुई। एडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि पत्र केवल जमीन की जांच और विभागीय प्रक्रिया से संबंधित है।अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।किसानों ने अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और एसडीएम सदर से मुलाकात कर अपनी बात रखी।इस मौके पर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण से इनकार किया, लेकिन किसानों ने भविष्य की कार्रवाई को लेकर लिखित आश्वासन की मांग की।

मुहर्रम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु बैठक आयोजित'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी मुहर्रम पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण

वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज बिस्मिल सभागार में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, पुलिस ।

मानसून से पहले नगर निगम अलर्ट, नगर आयुक्तने परखी तैयारियां

गोरखपुर, (संवाददाता)। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचाव के लिए नगर निगम ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त अजय जैन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न पंपिंग स्टेशनों और प्रमुख नालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नालों में गंदगी और अवरोध मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने डोमिनगढ़, इलाहीबाग, मिर्जापुर, हांसूपुर और तकियाघाट स्थित पंपिंग स्टेशनों का जायजा लेकर उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बारिश के समय जल निकासी व्यवस्था सुचारु रहे, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं। डोमिनगढ़ और इलाहीबाग के बड़े नालों में दोबारा सफाई की आवश्यकता मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को पोकलेन मशीन लगाकर व्यापक सफाई कराने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि नालों में जमा सिल्ट और कचरा पूरी तरह हटाया जाए, ताकि जल निकासी बाधित न हो। मिर्जापुर क्षेत्र में एक नाला खुला मिलने पर उसे तत्काल ढकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले नाले दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता अशोक भाटी, अवर अभियंता धीरज वर्मा व क्षेत्रीय पार्षद श्रवण पटेल आदि मौजूद रहे।

फर्जी फर्म और म्यूल खातों से 50 करोड़ की ठगी में दो गिरफ्तार, बिहार में घोटाले से जुड़ा तार

भदोही, (संवाददाता)। भदोही जिले की पुलिस ने मंगलवार को एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया। फर्जी ट्रेडिंग एवं इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाकर करीब 50 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाले गिरोह के दो सदस्य नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चकसिखारी निवासी ओमप्रकाश गौतम को बनकट छनौरा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के तार बिहार एनएचएआई के 32 करोड़ घोटाले से जुड़े हैं। जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना कर रही है। गिरोह के विरुद्ध एनसीआरपी के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि साइबर मामलों की जांच में पता चला कि नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चकसिखारी निवासी ओमप्रकाश गौतम के तार साइबर ठगी के एक गिरोह से जुड़े हैं। यह गिरोह फर्जी ट्रेडिंग एवं इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से देशभर में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी कर चुका है। पुलिस ने दोनों को बनकट छनौरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने 50 से अधिक म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर साइबर ठगी के आए पैसों को स्थानांतरित किया था। गिरोह के जुड़े विभिन्न खातों से 30 लाख से अधिक की धनराशि फ्रीज कराई गई। इनके पास से पांच मोबाइल फोन, सात जियो सिम कार्ड, पांच एटीएमध्डेबिट कार्ड, तीन पासबुक एवं तीन चेकबुक, दो फर्जी आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, दो बैंक खाता खोलने संबंधी फॉर्म, 43 आधार अपडेट फॉर्म समेत अन्य उपकरण बरामद हुए।

महिला एसओ आशा शुक्ला व समस्त कर्मियों ने किया योगाभ्यास

अयोध्या।महिला थाना परिसर मे प्रतिदिन महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला की अध्यक्षता मे महिला कर्मी योग कर रही है।इसी कडी मे गुरुवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला थाना परिसर मे तैनात सभी महिला पुलिस कर्मियों के साथ योगा अभ्यास किया।उन्होंने बताया महिला परिसर मे यह योगाभ्यास 21 जून तक चलता रहेगा।इस मौके पर उनके अलावा महिला उप निरीक्षक सोनी, प्रिया, श्वेता राठौर, सहित विमलेश,सायरा बानू,करिश्मा दूबे,वंदना, प्रेया सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

आस्था के नाम पर हुई लूट की सच्चाई लाई जाये देश के सामने - अजय राय

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।अयोध्या में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भाजपा–आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ष्आस्था के नाम पर हुई लूट की सच्चाई देश के सामने लाई जाए।उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि स्थित रामलला के दर्शन एवं पूजन के साथ हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेककर प्रदेश और देश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।अयोध्या जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही सहादतगंज में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतनारायण सिंह एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया।बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह जनसमर्थन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन की मजबूत जमीन तैयार हो चुकी है। कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश की गंगा–जमुनी संस्कृति, संविधान और जनता की आस्था के सम्मान की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धर्म और आस्था को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाकर उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाया है।पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन एवं उससे जुड़े आर्थिक मामलों पर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिलापूजन एवं जनसहयोग के नाम पर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं से भारी धनराशि एकत्र की गई, लेकिन आज तक उस धन का पारदर्शी और सार्वजनिक हिसाब देश के सामने नहीं रखा गया।श्री राय ने कहा कि भाजपा–आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा जनता की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर धन संग्रह किया गया और अब उसके उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के संबंध में जवाबदेही तय होनी चाहिए तथा उस समय जिम्मेदार पदों पर रहे लोगों को देश की जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े आर्थिक लेन–देन और भूमि खरीद मामलों में सामने आ रही जानकारियां अत्यंत गंभीर हैं और एक संगठित अनियमितता की ओर संकेत करती हैं।यह केवल आर्थिक पारदर्शिता का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक करे।उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जांच की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है,जिनकी निष्पक्षता को लेकर पहले से ही प्रश्न उठ रहे हैं। इससे जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।कहा कि अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर आस्था और धर्म के नाम पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूरे मामले में जवाब देने के बजाय तथ्यों को दबाने और मामले को भटकाने का प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के शीर्ष स्तर पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई, जिनका सीधा संबंध केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय से रहा है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं बच नहीं सकते।कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रामजनम भूमि मंदिर चढ़ावे में चोरी की घटना को हैवानियत की संज्ञा दी और कहा देश के करोड़ों रामभक्तो को इस घटना से गहरा आघात लगा है, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और देश की आस्था से जुड़े हर प्रश्न का जवाब मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि धर्म किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है और भगवान श्रीराम करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं। उनके नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या आर्थिक अपारदर्शिता को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह तथा जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने प्रदेशअध्यक्ष अजय राय को रामनामा पहनाकर, पुष्पगुच्छ प्रदान किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व जिला अध्यक्ष गण क्रमशः अशोक सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह,राम दास वर्मा, दयाशंकर तिवारी, अशोक सिंह मनऊंपुर, हरगाना तिवारी, हृदयनारायण मिश्रा, पंकज सिंह, राम अवध पासी, मनोज जायसवाल, राज प्रताप सिंह, रामकिशोर वर्मा, रामशंकर तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, रवींद्र कुमार, अनिल सिंह, प्रशांत पांडे, कबींद्र साहनी, सुरेंद्र सिंह सैनिक, रामसागर रावत, भीम शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, दीप कृष्ण वर्मा,विकास सिंह बिक्की, संतोष तिवारी, बृजेश रावत, रामेन्द्र त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, रेनू राय, नाजिश फातिमा, मो अमीरु, अम्बरीश पांडे, संजय तिवारी, संदीप सिंह गोलू, महिपाल सिंह, कैफियत अंसारी,तैयब खान, बीरबहादुर सिंह, अश्वनी सिंह मधुर, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, सतीश सिंह आदि रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।